गुजरात में अन्तर्राष्ट्रीय विमान घर की आवश्यकता थी। विमान घर की हवाई पट्टी 9000 फीट लम्बी है। अन्तर्राष्ट्रीय विमान घर के लिए 12000 फीट लम्बी हवाई पट्टी चाहिए। इस वजह से सरकार ने 1991 अप्रैल में एक लाख बावन हजार फी-मीटर जमीन सम्पादित की थी। लेकिन सरकार ने इस जमीन में से 78 हजार फी-मीटर जमीन प्राईवेट मकान बनाने के लिए बेच डाली। अभी वहां सोसायटीज बन रही है।

अहमदाबाद शहर के विकास में जिसका अंतर्राष्ट्रीय महत्व बढ़ाने वाला है वहां अब अंतर्राष्ट्रीय विमानघर न बने ऐसा प्रयत्न राजकीय हित रखने वाले तत्वों ने किया है। गुजरात की जनता के साथ दगा किया है। अहमदाबाद का अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। सरकार ने यह गंभीर गलती की है। अब फिर से विमान घर के लिए जमीन संचायित करना सरकार के लिए मुश्किल बन गया है। यदि फिर से जमीन संचायित करेगी तो गुजरात की जनता को करोड़ों रुपये देने पड़ेंगे। गुजरात की जनता सरकार को कभी माफ नहीं करेगी।

रनवे के लिए जमीन संचायित नहीं की गई तो अहमदाबाद में कभी भी अंतरारष्ट्रीय विमानघर नहीं बनेगा और विमानघर पर कभी भी जम्बो जेट जैसे विमान आ नहीं सकेंगे। प्रजा को इस सुविधा से वंचित रखने का किसी को अधिकार नहीं है।

मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि क्या यह बात आपकी जानकारी में है ? यदि है तो इसका ब्यौरा क्या होगा ? क्या जमीन फिर से संचायित करेंगे ? क्या अंतर्राष्ट्रीय विमानघर नहीं बनायेंगे ? अंतरराष्ट्रीय विमानघर कब बनेगा ? धन्यवाद।

श्री अनन्त राय वेवशंकर दवे (गुजरात): मैं इससे अपने को एसोसियेट करता हूं और एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि एयर पोर्ट अथारिटी ने जमीन ली थी और राज्य सरकार ने यह जमीन बेच डाली है या केन्द्रीय सरकार की जानकारी में यह है ? यदि है तो इस बारे में केन्द्र सरकार स्टेटमेंट दे। अगर रनवे के लिये जमीन नहीं ली गयी तो यहां कभी भी अंतराष्ट्रीय एयरपोर्ट नहीं बन सकता है।

Headiest Public Sector Undertakings

डा० मुरली मनोहर जोशी (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो सार्वजनिक उपक्रमों से संबंध रखता है की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय लगभग 35 स्थान ऐसे हैं कि जिसमें सार्वजनिक उपक्रमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नहीं हैं चीफ एक्जीक्यूटिव्स नहीं हैं। यहां तक कि जो उनको चयन करने वाला बोर्ड है पब्लिक इंटरप्राइजेज सलेक्शन बोर्ड, जो इस बात के लिये जिम्मेदार है कि वह सारे उपक्रमों के पदाधिकारियों को चयनित करें उसका भी कोई अध्यक्ष नहीं है, वह भी शीर्ष से खाली है। ये 35-36 संस्थायें बिल्कुल टापलेस आज पड़ी हुई हैं। इसका नतीजा यह है कि भारत के सारे उपक्रमों में भारी अव्यवस्था, भारी घाटा, भारी अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो गयी है। नेशनल टैक्सटायल कारपोरेशन, राष्ट्रीय कैमिकल एंड फर्टिलाइजर, स्कूटर्स इंडिया, भारत भारी उद्योग निगम नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, मझगांव डाक, नेशनल हाईड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन, गैस अथारिटी आफ इंडिया, सेंट्रल इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, बंगाल केमिकल्स, भारत लेदर कारपोरेशन इत्यादि बहुत सारे उपक्रम ऐसे हैं जिनमें सी० एम० डी० नहीं है। आज इसका नतीजा यह हो गया है कि एच० एम० टी० जैसी कंपनी को सरकार कह रही है कि वह धीरे-धीरे अपने घाटे को पूरा करने

के लिये अपने लिये प्राइवेट वेंचर करने वालों को ढूंढ़ ले। 1991-92 में यह संस्था बहुत अच्छी चल रही थी। उसमें किसी भी प्रकार का घाटा नहीं था, लेकिन धीरे-धीरे इसका घाटा बढ़ रहा है और अब यह कहा जा रहा है कि इसको पांच यूनिट्स में बांटकर इसको बेच दिया जाय। मैं अभी बंगलौर गया था। वहां के कर्मचारी मुझे मिले। उन्होंने आशंका व्यक्त की कि एच० एम० टी० जैसे कारखाने को जिसके बारे में स्वयं सरकार की रिपोर्ट है, जो इंडस्ट्री विभाग की रिपोर्ट है तो उस रिपोर्ट के अनैक्चर 4 में इसको 'गुड' काम करने वाली श्रेणी में रखा गया है। चार श्रेणियों में सारे उपक्रमों को बांटा गया है, एच० एम० टी० गुड श्रेणी में आती है लेकिन आज हालत यह हो गयी है कि आज एच० एम० टी० के कार्यकलाप भी संदेह के घेरे में आ गए हैं। वहां के लोगों में भारी आशंका पैदा हो गयी है।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या सार्वजनिक उपक्रमों के बारे में सरकार की कोई नीति है कि इनमें से किनको बेचा जायेगा, कब बेचा जायेगा और क्यों बेचा जायेगा? क्या उनको लाभकारी बनाने के लिये सरकार की कोई नीति है? अगर 35 इस प्रकार के कारखाने हैं जिनमें सी० एम० डी० नहीं है तो उनसे हम लाभ की आशा क्या कर सकते हैं? दो हजार करोड़ रुपये से ऊपर देश के सारे उपक्रमों में लगे हुए हैं लेकिन वे 10 प्रतिशत या 5 प्रतिशत भी मुनाफा नहीं दे रहे हैं।··· (व्यवधान)·· प्रादेशिक सरकारों के भी हैं। सभी मिलाकर उद्योगों में इतना लगा हुआ है। सार्वजनिक उपक्रमों में, पब्लिक अंडरटेकिंग्स में और पब्लिक इंटरप्राइसेज में अगर आप देखें तो सरकार ने पिछले सालों ही में 33 हजार करोड़ रुपया सार्वजनिक उपक्रमों में इनवेस्ट किया है। अगर आप राज्य को भी देखेंगे तो मैं समझता हूं कि 2 लाख से भी ऊपर जायेगा जो कि कम नहीं है। आज इम्पलाईमेंट घट रहा है। आज परिस्थिति यह है कि सरकार को इसके बारे में नीति का निर्धारण करना है या नहीं करना है? वहां के कर्मचारियों के भविष्य के बारे में क्या विचार करना है? उनको लाभकारी कैसे बनाया जाय इसके बारे में क्या विचार करना है?

मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि 35 कार्यकारी अधिकारियों को, सी० एम० डीज० को कब तक नियुक्त करेंगे और उसमें जो बाधाएं हैं उनको कैसे दूर करेंगे? क्या सरकार की यह नीति है कि धीरे-धीरे इस तरह से इनको टॉपलेस छोड़ दो, बिक जाएं तो बिक जाएं भगवान के वास्ते। मेरा अनुरोध यह होगा कि बहुत महत्वपूर्ण मसला देश की अर्थ-व्यवस्था से संबंधित है, रोजगार से संबंधित है, कंपीटीटिवनेस से संबंधित है और नयी लिबरलाइजेशन एंड रीस्ट्रक्चरिंग से संबंधित है। आप इस पर स्पष्ट नीति निर्धारण करें। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय यहां पर आएं और इस के बारे में सदन को आश्वस्त करें कि वह इस बड़ी भारी देश की अर्थ-व्यवस्था के बारे में, इनवेस्टमेंट के बारे में और प्रोडक्टीविटी के बारे में क्या निर्णय लेते हैं और किस तरह से इसको ठीक करेंगे। धन्यवाद।

SHRI MD. SALIM (West Bengal) : Sir, I associate myself with Dr. Joshi. Earlier also, when the same issue was raised in the form of question-answer and by way of Special Mentions, the Government promised that they would appoint CMDs in various public sector undertakings. What Dr. Joshi mentioned just now only goes to show the attitude of the Government in allowing the public sector undertakings to function without CMDs so that it would become easy for them to liquidate these public sector undertakings. Secondly, as Dr. Joshi also mentioned, these public sector undertakings have stopped recruiting staff under the guise of rationalisation or, what they call, proper utilisation of manpower. And they show,